जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 182 प्रभात हिण्डौन सिटी, सोमवार 4 मई, 2026 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ईरान के चाबहार पोर्ट का लाभ किसी भी सूरत में नहीं खोना चाहता भारत

पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान व सैन्ट्रल एशिया के मार्केट को पकड़ने के लिए चाबहार की बड़ी अहमियत है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मई। भारत के लिए रणनीतिक चाबहार बंदरगाह परियोजना एक सपना थी, क्योंकि इससे वह पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे पहुँच सकता था। अब, अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट समाप्त होने के बाद, ये उम्मीदें संकट में हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के पास अभी भी एक ट्रिक बची है।

उत्तर-पश्चिम में शत्रुदेश पाकिस्तान के होने का अर्थ है कि भारत को अफगानिस्तान और लाभप्रद मध्य एशियाई बाजार तक सीधा मार्ग न मिले। इस बाधा को पार करना जरूरी था। वर्ष 2003 में भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट विकसित करने के लिए बातचीत शुरू की। एक दशक बाद, बंदरगाह के दो टर्मिनलों में से एक का संचालन करने के लिए साझेदारी

- **अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह प्रोजैक्ट पर प्रतिबंध लगाकर छूट दी हुई थी। यह छूट गत सप्ताह समाप्त हो गई। इससे चाबहार प्रोजैक्ट के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं।**
- **भारत ने "टैक्नीकल प्रेगमैटिज़्म" की नीति अपनाते हुए इस गतिरोध को दूर करने का रास्ता निकाला है। भारत अस्थाई रूप से चाबहार प्रोजैक्ट की अपनी हिस्सेदारी एक ईरानी की ईकाई को ट्रांसफर करेगा, प्रतिबंध काल के लिए। जब प्रतिबंध हट जाएंगे तो पोर्ट का नियंत्रण वापस भारत के पास आ जाएगा।**
- **अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से टकराव से बचते हुए जियो पोलिटिकल वास्तविकता के साथ संतुलन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की विशेषता मानी जाती है।**

औपचारिक रूप से स्थापित की गई।

लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में परियोजना पर लगाए गए प्रतिबंधों पर अमेरिकी छूट की अवधि समाप्त होने के साथ ही, भारत फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। यहीं पर दिल्ली ने मास्टरस्ट्रोक खेला।

सीमित विकल्पों के बीच, भारत अब अपनी हिस्सेदारी अस्थायी रूप से एक स्थानीय ईरानी इकाई को हस्तांतरित करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यवस्था में ईरानी इकाई प्रतिबंधों की अवधि के दौरान, संचालन का प्रबंधन करेगी। जब प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, नियंत्रण वापस भारत के पास जाएगा। विशेषज्ञ इसे "रणनीतिक व्यावहारिकता" (टैक्टिकल प्रैगमैटिज़्म) कह रहे हैं।

यह संकेत देता है कि दिल्ली लंबी अवधि के लिए तैयार है, जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच खेलते समय धैर्य बनाए रखा जाता है।

यही भारत की खेल योजना है। इस योजना के अनुसार, भारत चाबहार से पीछे भी नहीं हटेगा, तथा ट्रम्प के साथ टकराव से भी बच जायेगा। यह वही कला है, जिसे भारत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक सनकी अमेरिकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

होर्मुज़ पर ईरान नये कानून की तैयारी में

तेहरान, 03 मई। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान अब होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हमीदरेजा हाजी-बाबाई ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित कानून के तहत इज़रायल से जुड़े जहाजों के इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने पर रोक लगाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में दुश्मन देशों के जहाजों के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। ऐसे जहाजों को जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए युद्ध से जुड़े नुकसान की भरपाई

- **इज़रायल से जुड़े जहाजों के गुजरने पर रोक तथा दुश्मन देशों के जहाजों से युद्ध से नुकसान की भरपाई के संकेत।**

करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही अन्य देशों के जहाजों को भी ईरान से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जा सकता है।

हाजी-बाबाई के मुताबिक, युद्ध के बाद क्षेत्रीय हालात बदल चुके हैं और अब होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही पहले जैसी नहीं रहेगी। उनका कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है।

अगर यह कानून लागू होता है तो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजा

ट्रंप ने कहा कि लगता नहीं ईरान से बात बन पाएगी, शांति प्रस्ताव की गहराई से समीक्षा करेंगे

वाशिंगटन/दोहा/तेहरान, 03 मई। ईरान ने अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव 14 सूत्रीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि यह प्रस्ताव मिल चुका है। उन्होंने शनिवार को पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर पत्रकारों को यह जानकारी दी। ट्रंप ने साफ किया कि उन्हें अभी भी नहीं लग रहा कि ईरान से बात बन पाएगी। उन्होंने कहा कि वे शांति प्रस्ताव की गहराई से समीक्षा करेंगे। इस बीच अमेरिका-इज़रायल के फरवरी के आखिर में किए गए सैन्य हमले के बाद होर्मुज़ जलडमरूमध्य में संकट लगातार गहरा रहा है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान के विदेशमंत्री से सूझबूझ से काम लेने की सलाह दी है।

सीबीएस न्यूज, फॉक्स न्यूज, अल जजीरा और तसनीम की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि ईरान ने अभी-अभी प्रस्ताव भेजा है। बावजूद इसके उन्हें नहीं लगता कि ईरान समझौता कर पाएगा। इसमें आक्रमण न करने की गारंटी, नाकाबंदी हटाने और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा, "मैंने इसे अभी देखा नहीं है। मैं प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा। इसके बाद ही हमारे रुख की मीडिया को

- **ईरान के प्रस्ताव में आक्रमण नहीं करने की गारंटी, नाकाबंदी हटाने तथा लेबनान सहित, मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की माँग की गई है।**
- **निक स्टीवर्ट ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए काम कर रही टीम में शामिल हो गए हैं। वे तेजतर्रार और अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में वे विदेश विभाग के सदस्य थे।**

आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।

ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के कुछ समय बाद ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मुझे नहीं लगता कि ईरान का शांति प्रस्ताव स्वीकार्य होगा। ईरान ने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए उसने अभी पूरी कीमत नहीं चुकाई है। उन्होंने कहा कि ईरान में सब कुछ तबाह हो चुका है। वह समझौता करने के लिए लालायित है।" उन्होंने दुहराया कि अगर अमेरिका ईरान से हट भी जाए तो भी तबाह हुए मुल्क को खड़ा होने में 20 साल लग जाएंगे।

ट्रंप ने कहा, मुश्किल यह है कि यही समझ में नहीं आ रहा कि इस समय ईरान का सर्वमान्य नेता कौन है। कभी कोई आगे आ जाता है तो कभी कोई। ऐसी स्थिति में इस बात की पक्की संभावना है कि अमेरिका फिर से कुछ ठिकानों पर सैन्य हमले शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने कोई बेजा हरकत की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप की हमले की टिप्पणी के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि वह अमेरिका के साथ फिर से युद्ध के लिए तैयार है।

इस बीच वाइट हाउस ने शनिवार को पुष्टि की कि निक स्टीवर्ट ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम में शामिल हो गए हैं। वे राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान विदेश विभाग के सदस्य रहे हैं। वे तेजतर्रार और अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। वे विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की प्रतिभाशाली टीम के अहम सदस्य हैं।

इस सैन्य घमासान से चिंतित कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत व चीन के कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालन पर नेपाल ने आपत्ति जताई

बालेन सरकार ने दोनों देशों को पत्र लिख कर नेपाल की भूमि पर सड़क निर्माण, व्यापार व तीर्थयात्रा नहीं करने को कहा

काठमांडू, 03 मई। नेपाल की बालेन सरकार ने लिपुलेक पास से भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालन किए जाने पर आपत्ति जताते हुए दोनों देशों को कूटनीतिक पत्र भेजा है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने जानकारी दी कि नेपाल सरकार ने लिपुलेक क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालन करने की योजना पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराते हुए भारत और चीन, दोनों को पत्र भेजा है।

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने फोन पर बताया कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने के बाद

- **नेपाल सरकार ने कहा कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, महाकाली नदी के पूर्व स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी नेपाल के अभिन्न भूभाग हैं और इस विषय पर नेपाल सरकार पूरी तरह स्पष्ट और अडिग है।**

नेपाल की आधिकारिक स्थिति दोनों देशों को अवगत करा दी गई है।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञिप्त में कहा गया है कि नेपाली भूमि लिपुलेक के माध्यम से प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में नेपाल सरकार ने अपना स्पष्ट रुख और चिंता भारत तथा चीन, दोनों पक्षों को कूटनीतिक माध्यम से पुनः जानकारी करा दी है।

सरकार ने यह भी दोहराया है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, महाकाली नदी के पूर्व स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी नेपाल के अभिन्न भूभाग हैं और इस विषय पर नेपाल सरकार पूरी तरह स्पष्ट और अडिग है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने विश्व का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च किया

नई दिल्ली, 03 मई। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को दुनिया के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट "मिशन दृष्टि" के सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। बंगलूरू स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सआई ने इस उपग्रह को बनाया है।

- **आधुनिक तकनीक का यह उपग्रह किसी भी मौसम/बादलों के बीच व रात के अंधेरे में धरती की स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है।**

गैलेक्सआई के मिशन दृष्टि उपग्रह को रविवार को कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। यह भारत में किसी निजी संस्थान की ओर से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है।

प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को भारत के लिए गौरवशाली बताया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा के झंडे वाले दो वाहनों को मतगणना परिसर में प्रवेश दिया गया- टीएमसी

निर्वाचन आयोग ने कहा, वाहन पास की सड़क से गुजर रहा था, जिसे जाँच के बाद जाने दिया गया

कोलकाता, 03 मई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केन्द्र के बाहर रविवार को हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के झंडे वाले दो वाहनों को उस परिसर में प्रवेश दिया गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) रखी गई हैं।

यह घटना उस समय हुई, जब इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने सखावत बालिका विद्यालय में स्थित इस मतगणना केन्द्र के बाहर चार घंटे तक धरना दिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में अनधिकृतिक लोगों के प्रवेश का आरोप लगाया था।

मतदान खत्म होने के बाद अब

- **एक दिन पहले ममता बनर्जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सखावत बालिका विद्यालय स्थित मतगणना केन्द्र पर चार घंटे धरना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्ट्रॉन्ग रुम में अनधिकृत लोगों को प्रवेश दिया गया।**

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सत्ता को लेकर तनाव बढ़ गया है। दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता राज्य भर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर नजर रखे हुए हैं, जहां उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद है। भारी जीत का भरोसा जताने के बावजूद, ममता बनर्जी ने कई बार मतगणना में गड़बड़ी और ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है।

रविवार सुबह टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के झंडे लगी दो गाड़ियां परिसर में घुसीं और स्ट्रांग रूम के पास तक पहुंच गईं। एक कार्यकर्ता ने कहा कि बिना पहचान पत्र के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिर भी इन वाहनों को कैसे प्रवेश मिला। टीएमसी ने दावा किया कि पुलिस ने वाहनों को हटाने का भरोसा दिलाया। लेकिन वे कुछ समय तक वहां खड़े रहे।

हालांकि, निर्वाचन आयोग के एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मणिपुर : बम हमले में मरे दो मासूमों का 25 दिन बाद अंतिम संस्कार

नई दिल्ली, 03 मई। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में ट्रोंग्लाओबी घटना में जान गंवाने वाले दो मासूम बच्चों का अंतिम संस्कार 25 दिन बाद किया गया। इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल को मोइरांग के ट्रोंग्लाओबी अवांग लीकेई इलाके में स्थित एक घर

- **गत 7 अप्रेल को एक घर पर उग्रवादियों द्वारा फेंके बम से दो बच्चों की मौत हुई थी।**

पर संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा बम फेंका गया था। इस हमले में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

लंबे समय तक चले हालात और प्रक्रियाओं के बाद, अब जाकर दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान इलाके में माहौल बेहद गमगीन रहा और लोगों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

होर्मुज़ से एक और भारतीय जहाज निकला

नई दिल्ली, 03 मई। मिडिल ईस्ट में परेशानी चल रही है, लेकिन भारत के लिए राहत की खबर है। भारत के लिए गैस लेकर आ रहा जहाज सर्व शक्ति समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पार कर गया है। ये जहाज मार्शल द्वीप के नाम से रजिस्टर्ड है। सरकार के अनुसार,

- **46 हजार टन एलपीजी से भरा जहाज 13 मई को विशाखापट्टनम पहुँचेगा।**

जहाज 13 मई को विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा। मतलब, भारत को जरूरी गैस बिना किसी रुकावट के मिल जाएगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस जहाज में करीब 46 हजार मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है। जहाज पर कुल 20 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से 18 भारतीय हैं। मिडिल ईस्ट के टेंशन और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में रुकावट को लेकर सरकार ने यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए ट्रंप ने क्यूबा पर कब्जा करने की घोषणा की

गत एक माह से अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा पर बड़े रिफॉर्म करने या सैन्य कार्यवाही का सामना करने की धमकी दे रहे हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मई। अपने देश में तेजी से गिरती लोकप्रियता को रोकने के प्रयास में, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने भ्रमित करने वाले संकेत दिए हैं। एक ओर उन्होंने धमकी दी कि अमेरिका की नौसेना ईरान से वापसी के रास्ते में क्यूबा को निशाना बनाएगी, तो दूसरी ओर उन्होंने आपातकाल का हवाला देकर कांग्रेस की समीक्षा को दरगुज़र करते हुए मिडिल ईस्ट देशों को हथियार देने की मंजूरी दे दी।

ईरान को लेकर ट्रम्प यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि वे सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेंगे या तेहरान के प्रस्तावों को स्वीकार करेंगे। हाल ही में, शाम पाम बीचेज़ के नॉन-प्रॉफिट फोरम क्लब में अपने भाषण में उन्होंने कहा, "क्यूबा में कई समस्याएं हैं।"

उन्होंने कहा, "ईरान से लौटते समय हमारा बड़ा विमानवाहक पोत, शायद यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, हमारे पास आएगा, यह तट से लगभग 100 गज दूर रुकेगा और वे कहेंगे, "बहुत धन्यवाद। हम हार मानते हैं।"

ट्रम्प प्रशासन वर्तमान में क्यूबा सरकार पर जोर डालने के लिए महीनों से अभियान चला रहा है कि वह बड़े पैमाने पर नाटकीय रिफॉर्म्स करे।

इसके साथ ही, ट्रम्प ने बार-बार धमकी दी है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अमेरिका इस द्वीप पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

ट्रम्प नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने मिडिल ईस्ट देशों को हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी, कांग्रेस की समीक्षा को दरगुज़र करते हुए उन्होंने इसके लिए आपातकाल का हवाला दिया।

- **दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने इज़रायल, कतर और कुवैत को 8.6 मिलियन डॉलर से अधिक हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी।**
- **"आपातकालीन स्थिति" तथा "अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों" के नाम पर ट्रंप प्रशासन ने आवश्यक कांग्रेस स्वीकृति से बचकर तुरंत हथियार सप्लाई करने का निर्णय लिया।**
- **जहाँ एक ओर वॉशिंगटन ने अपने मिडिल ईस्ट सहयोगियों को हथियार देकर समर्थन जारी रख रहा है, दूसरी ओर नाटो देशों के साथ उसके मतभेद बढ़ रहे हैं।**

यह सैन्य बिक्री, जो कुल 8.6 बिलियन डॉलर से अधिक की है, हवाई रक्षा मिसाइलों से लेकर लेज़र गाइडेंस सिस्टम तक फैली हुई है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में को इसकी घोषणा की, जबकि अमेरिका और इज़रायल का ईरान पर युद्ध नवें सप्ताह में प्रवेश कर गया है, और संघर्ष समाप्ति पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, भले ही एक अस्थिर संघर्ष विराम लागू हो।

विदेश विभाग ने इज़रायल को 10,000 एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम-छ्छ ऑल अप राउंड्स और संबंधित उपकरणों की बिक्री की अनुमति दी, जिसकी कीमत 992.4 मिलियन डॉलर है, और इसे बीएई सिस्टम द्वारा निर्मित किया गया है।

अमेरिका ने कतर को 10,000 एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम-छ्छ ऑल-अप-राउंड्स (सिंगल वेरिएंट) सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी, जिसकी कीमत 992.4 मिलियन डॉलर है। इस संभावित बिक्री का मुख्य ठेकेदार बीएई सिस्टम्स होगा।

कतर ने 200 पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी-2 (पीएसी-2) गाइडेंस एन्हांस्ड मिसाइल-टैक्टिकल इंटरसेप्टर और 300 पीएसी-3 मिसाइल सेगमेंट एन्हांसमेंट इंटरसेप्टर और संबंधित उपकरण खरीदे, जिसकी कुल कीमत 4.01 बिलियन डॉलर है। लॉकहीड और आरटीएक्स इसके मुख्य ठेकेदार हैं।

यूएई को 1,500 गाइडेंस सैक्शन, सिंगल वेरिएंट (एयर-टू-एयर), एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम-छ्छ की बिक्री की अनुमति दी गई, जिसकी कुल लागत 147.6 मिलियन डॉलर है।

रॉयटर्स ने बताया, कुवैत की 2.5 बिलियन डॉलर की खरीद के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अग्रिम जमानत मिलने के बाद खेड़ा दिल्ली पहुँचे

नई दिल्ली, 03 मई। उच्चतम न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने खेड़ा का फूल-

- **हवाई अड्डे व पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं व नेताओं ने उनका स्वागत किया।**

मालाओं के साथ स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे इंदिरा भवन पहुंचे।

पत्रकारों से बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है लेकिन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान हमेशा संकट के समय में सहारा देता है। जब भी कोई व्यक्ति मुश्किल में होता है या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)